कथौड़ी जनजाति के सामाजिक व आर्थिक विकास का भौगोलिक अध्ययन

सन्तोष कँवर, डॉ चन्द्रशेखर जैमन

सार: यह अध्ययन कथौड़ी जनजाति के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के भौगोलिक आयामों की पड़ताल करता है, जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (च्टज्ळ) है और मुख्य रूप से पश्चिमी भारतीय राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में रहता है। नृवंशविज्ञान क्षेत्र कार्य, स्थानिक विश्लेषण और सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षणों के संयोजन वाले एक बहु–विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से, शोध भौगोलिक स्थान, प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच और विकास के पैटर्न के बीच परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालता है। अध्ययन साक्षरता स्तर, रोजगार पैटर्न, भूमि स्वामित्व, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच और आवासीय स्थिति जैसे प्रमुख संकेतकों की जाँच करता है। यह जनजाति की सामाजिक–आर्थिक प्रगति पर सरकारी कल्याण योजनाओं और वन–आधारित आजीविका के प्रभाव पर भी विचार करता है। निष्कर्ष भौगोलिक हाशिए पर होने, सीमित बुनियादी ढाँचे और सामाजिक बहिष्कार में निहित लगातार विकासात्मक चुनौतियों को उजागर करता हैं।

मुख्य शब्द: कथौड़ी, जनजाति, आर्थिक, विकास, सर्वेक्षण

परिचय

भारत में कई तरह के आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनमें से कई ऐतिहासिक, सामाजिक और भौगोलिक रूप से हाशिए पर हैं। इनमें से, कथौड़ी जनजाति, जिसे विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह (च्टज्ळ) के रूप में पहचाना जाता है, एक अलग स्थान रखती है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के जंगली और पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले कथौड़ी लोगों का नाम काठ से लिया गया है, जो बबूल के पेड़ों से निकलने वाले कत्थे के अर्क को संदर्भित करता है – एक पारंपरिक व्यवसाय जिसने उनकी आर्थिक पहचान को काफी हद तक परिभाषित किया है। इस विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत के बावजूद, जनजाति को लगातार विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कथौड़ी जनजाति का भौगोलिक वितरण उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। दूरदराज के, अक्सर पारिस्थितिक रूप से कमज़ोर क्षेत्रों में रहने के कारण, उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोज़गार के अवसरों तक सीमित पहुँच है। बुनियादी ढाँचे के विकास की कमी, वन उपज और पारंपरिक आजीविका पर जनजाति की ऐतिहासिक निर्भरता के कारण सामाजिक–आर्थिक ठहराव हुआ है। इसके अलावा, वनों की कटाई, विकास परियोजनाओं और पर्यावरण नीतियों के कारण विस्थापन ने उनकी पारंपरिक जीवन शैली को और कमज़ोर कर दिया है। यह अध्ययन कथौड़ी जनजाति के विकास के स्थानिक आयामों की जांच करता है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि भूगोल बुनियादी सेवाओं तक उनकी पहुँच और मुख्यधारा के समाज में एकीकरण को कैसे प्रभावित करता है। जनसांख्यिकीय पैटर्न, भूमि उपयोग, व्यावसायिक संरचनाओं और गतिशीलता की जांच करके, शोध का उद्देश्य पर्यावरण, नीति और सामाजिक–आर्थिक परिणामों के बीच जटिल अंतर्संबंधों को उजागर करना है। इसके अलावा, अध्ययन विकास के अंतर को पाटने में आदिवासी कल्याण योजनाओं, आवास परियोजनाओं और शैक्षिक पहलों जैसे सरकारी हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। जबकि कुछ प्रगति देखी गई है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां गैर सरकारी संगठन और स्थानीय शासन संरचनाएं सक्रिय हैं, प्रणालीगत चुनौतियां बनी हुई हैं। भौगोलिक लेंस के माध्यम से, यह शोध कथौड़ी जनजाति के सामाजिक–आर्थिक विकास की समग्र समझ प्रदान करने का प्रयास करता है। यह आदिवासी विकास में स्थानिक और पर्यावरणीय कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करके अकादमिक प्रवचन में योगदान देना और नीतिगत निर्णयों को सूचित करना चाहता है। व्यापक लक्ष्य संदर्भ–संवेदनशील, समावेशी विकास रणनीतियों की वकालत करना है जो संधारणीय प्रगति को बढ़ावा देते हुए कथौड़ी लोगों की पारिस्थितिक और सांस्कृतिक अखंडता का सम्मान करते हैं।

भारत के आदिवासी समुदाय लंबे समय से अकादमिक जांच, नीतिगत चिंता और विकासात्मक हस्तक्षेप का विषय रहे हैं। फिर भी, ऐसे कई समुदाय, विशेष रूप से कथौड़ी जैसे च्टज्ळ के रूप में वर्गीकृत, कम मानव विकास सूचकांक (भ्क्) संकेतक, उच्च निर्भरता अनुपात और शासन तंत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का अनुभव करना जारी रखते हैं। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में अपनी भौगोलिक सांद्रता के कारण कथौड़ी जनजाति मुख्यधारा के विकास प्रक्रियाओं के हाशिये पर बनी हुई है। कथौड़ी के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों में से एक वन संसाधनों पर उनकी ऐतिहासिक निर्भरता है, विशेष रूप से कैटेचू का निष्कर्षण, जो वन विनियमों, वृक्ष आवरण की कमी और बाजार में बदलाव के कारण आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो गया है। अपने पारंपरिक आर्थिक आधार के क्षरण के साथ, जनजाति को बढ़ती भेद्यता का सामना करना पड़ा है। कई सदस्य अब प्रवासी मजदूरों, आकस्मिक कृषि श्रमिकों या अकुशल शहरी श्रमिकों के रूप में काम करते हैं, अक्सर शोषणकारी परिस्थितियों में। भौगोलिक दृष्टिकोण से, कथोडी बस्तियों का स्थलाकृतिक अलगाव सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी पहुँच को काफी प्रभावित करता है।

पीने का पानी, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सेवा केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाएँ अक्सर अनुपस्थित या अपर्याप्त होती हैं। यह भौतिक दुर्गमता सरकारी योजनाओं जैसे एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (आईटीडीपी), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत आवास और खाद्य सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन और निगरानी को भी प्रभावित करती है। शिक्षा चिंता का एक और प्रमुख क्षेत्र है। जबकि कथौड़ीयो के बीच साक्षरता दर धीरे–धीरे सुधर रही है, बच्चों के बीच स्कूल छोड़ने की दर उच्च बनी हुई है, खासकर लड़कियों के बीच। स्कूल अक्सर बस्तियों से दूर स्थित होते हैं, और सांस्कृतिक और आर्थिक कारक निरंतर स्कूली शिक्षा को हतोत्साहित करते हैं। भाषाई बाधाएं, प्रासंगिक पाठ्यक्रम की कमी और शिक्षा की खराब गुणवत्ता शैक्षिक विभाजन को और बढ़ाती है। सामाजिक रूप से कथौड़ीयो को गैर–आदिवासी समुदायों और नीति कार्यान्वयन के व्यापक ढांचे के भीतर भेदभाव और

सन्तोष कँवर, शोधार्थी अपेक्स विश्वविद्यालय,जयपुर
डॉ चन्द्रशेखर जैमन, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग

बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। जाति, वर्ग और आदिवासी पहचान का प्रतिच्छेदन शासन की संस्थाओं के साथ उनकी बातचीत को जटिल बनाता है।

कथौड़ी जनजाति

राजस्थान की कुल कथौड़ी आबादी का 52 प्रतिशत कथौड़ी जनजाति उदयपुर की कोटडा, झाडोल व सराड़ा पंचायत समिति में बसे है शेष मुख्यतः डूंगरपुर, बारां व झालावाड़ में बसे है। ये महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं। खैर के पेड़ से कत्था बनाने में दक्ष होने के कारण वर्षों पूर्व उदयपुर के कत्था व्यवसायियों ने इन्हें यहाँ लाकर बसाया। कत्था तैयार करने में दक्ष होने के कारण ये कथौड़ी कहलाये। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कथौड़ी जनजाति की कुल आबादी मात्र 4833 है। वर्तमान में यह संकटग्रस्त जनजाति है इस हेतु राजस्थान सरकार ने मनरेगा में विशेष लाभ देते हुए इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करती है। वर्तमान में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई व पर्यावरण की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा इस कार्य को प्रतिबंधित घोषित कर दिए जाने के बाद कथौड़ी जनजाति की आर्थिक स्थिति बड़ी शोचनीय एवं बदतर हो गयी है। आज यह जनजाति समुदाय जंगल में लघु वन उपज जैसे बांस, महुआ, शहद, सफेद मूसली, डोलमा, गोद, कोयला एकत्र कर और चोरी की हुई लकड़ियाँ काटकर बेचने तक सीमित हो गया है। राज्य की अन्य सभी जनजातियों की तुलना में इस जनजाति के लोगों का शैक्षिक एवं आर्थिक जीवन स्तर अत्यधिक निम्न है।

भारत में जनजातीय विकास

वेरियर एल्विन (1959) जैसे विद्वानों के आधारभूत कार्य ने आदिवासी समुदायों के सांस्कृतिक संरक्षण पर जोर दिया और बिना किसी समावेश के विकास की वकालत की। बाद में, धेबर आयोग (1961) और ज़ाक्सा (2005) ने जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक नुकसान को पहचानते हुए, मुख्यधारा के विकास में उनके एकीकरण की ओर ध्यान केंद्रित किया। मुंशी (2010) और राव (2013) जैसे कई अध्ययनों ने आदिवासी आबादी के बीच लगातार गरीबी, खराब स्वास्थ्य और कम साक्षरता को उजागर किया, खासकर भौगोलिक रूप से दूरदराज और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में।

भूगोल और जनजातीय हाशिए पर

भूगोल जनजातीय विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिंह (2002) ने उल्लेख किया कि पहाड़ी या वन क्षेत्रों में स्थित जनजातियों को अक्सर भौतिक दुर्गमता के कारण राष्ट्रीय विकास प्रक्रियाओं से बाहर रखा जाता है। चक्रवर्ती (2014) ने तर्क दिया कि स्थानिक अलगाव सामाजिक बहिष्कार को मजबूत करता है, जिससे वंचना का एक चक्र बनता है। जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार तक उनकी पहुँच खराब होती है, जिससे गरीबी और बढ़ती है। यह विशेष रूप से कथौड़ी के लिए प्रासंगिक है, जो सीमित कनेक्टिविटी वाले आंतरिक वन क्षेत्रों में रहते हैं।

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (च्टज्ळे)

भारत सरकार द्वारा 1975 में पीवीटीजी की अवधारणा को उन आदिवासी समुदायों की पहचान करने के लिए पेश किया गया था, जिनके पास कृषि–पूर्व तकनीक का स्तर, स्थिर जनसंख्या वृद्धि और अत्यधिक सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन है। कथौड़ीयो को कैटेचू संग्रह पर उनकी आर्थिक निर्भरता और उनके अत्यधिक कमजोर आजीविका आधार के कारण पीवीटीजी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। मिश्रा और दास (2016) ने इस बात पर जोर दिया कि पीवीटीजी को उनके विशिष्ट सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संदर्भों पर विचार करने वाले के अनुरूप नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

कथौड़ी जनजाति की सामाजिक–आर्थिक स्थिति

कथौड़ी जनजाति पर विशेष रूप से केंद्रित अध्ययन सीमित हैं, लेकिन क्षेत्रीय सर्वेक्षणों और केस स्टडीज़ से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सक्सेना (2004) ने पाया कि गुजरात और महाराष्ट्र में कथौड़ी लोगों की साक्षरता दर बेहद कम थी, पोषण की स्थिति खराब थी और वे अक्सर भूमिहीन थे। देशपांडे (2011) ने उल्लेख किया कि जबकि वन नीतियों का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना था, उन्होंने अनजाने में कथौड़ी जैसी वनवासी जनजातियों के आर्थिक आधार को बाधित कर दिया। चौहान और सिन्हा (2018) ने देखा कि विस्थापन, वन प्रतिबंध और बाजार में उतार–चढ़ाव के कारण कथौड़ी लोगों के बीच संकटपूर्ण प्रवास में वृद्धि हुई है।

सरकारी हस्तक्षेप और अंतराल

भारत सरकार ने कई आदिवासी विकास कार्यक्रम लागू किए हैं, जिनमें एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ (आईटीडीपी), वनबंधु कल्याण योजना और लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) शामिल हैं। हालाँकि, गायकवाड़ (2020) ने बताया कि ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन में अक्सर सूक्ष्म–स्तरीय भौगोलिक और सामाजिक–सांस्कृतिक विशिष्टताओं की अनदेखी की जाती है। कथौड़ीयो के लिए, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन अधिकारों का कम क्रियान्वयन किया जाता है, जिससे उनकी भूमि असुरक्षा में योगदान होता है।

गैर सरकारी संगठनों और समुदाय–आधारित हस्तक्षेपों की भूमिका

कई जमीनी स्तर के संगठनों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के लिए कथोडी और अन्य आदिवासी समूहों के साथ काम किया है। बनर्जी और सिन्हा (2017) ने महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में समुदाय–आधारित वन प्रबंधन और माइक्रोफाइनेंस की सफलता पर प्रकाश डाला। हालाँकि, इन स्थानीय दृष्टिकोणों को स्थायी प्रभाव डालने के लिए लगातार सरकारी नीति के माध्यम से बढ़ाया और समर्थित किया जाना चाहिए।

नीति नियोजन में भौगोलिक एकीकरण की आवश्यकता

साहित्य में आदिवासी विकास नियोजन में स्थानिक विश्लेषण और जीआईएस उपकरणों को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। शर्मा एट अल. (2019) ने प्रदर्शित किया कि कैसे आदिवासी बस्तियों का स्थानिक मानचित्रण बुनियादी ढांचे की कमियों को पहचानने और कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लक्षित करने में मदद कर सकता है। कथोडी जैसे पीवीटीजी के लिए, भौगोलिक डेटा स्थानीय भूभाग, संसाधन उपलब्धता और बस्तियों के पैटर्न के प्रति संवेदनशील हस्तक्षेपों को अनुकूलित करने में सहायक हो सकता है।

अध्ययन क्षेत्र

जनजाति उपयोजना क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टि से जनजाति उपयोजना क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान के सम्पूर्ण बांसवाडा, डूंगरपुर प्रतापगढ़ (छोटी सादडी, छोडकर) सिरोही जिले के आबुरोड उपखण्ड तथा उदयपुर जिले की खेरवाड़ा, कोटड़ा, झाड़ोल, सलुम्बर, सराडा, तथा गिर्वा तहसील के 81 गांवा की समाहित करता है। 23 पंचायत समितियों तथा 19 तहसीलों के 4409 गांवों का 19770 वर्ग इस क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्व गाँव उपयोजना क्षेत्र 23°1′ उत्तरी अंक्षाश से 25°45′ 30′ अक्षांश तथा 73° पूर्वी देशान्तर से 74° 45 श पूर्वी देशान्तर तक उच्चावच की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र तीन भागों में विभक्त है

(अ) दक्षिणी अरावली ।
(ब) छप्पन का मैदान ।
(स) माही बेसिन का लगभग 40 % भूभाग पहाड़ी तथा पठारी ।

राजस्थान का प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल माउण्ट आबू तथा सबसे ऊँचा पर्वत शिखर गुरू शिखर (1722 मी.) सामाजिक व धार्मिक पर्यटन स्थल बेणेश्वर धाम जो आदिवासियों का महाकुंभ एवं मानगढ धाम, घोटिया अम्बा, इसी क्षेत्र में स्थित है माही, सोम, जाखम, साबरवमली, नदीयों का उद्‌गम भी इसी क्षेत्र से है।

अध्ययन की आधार सामग्री इस शोध पत्र में द्वितीय आंकड़ो का संकलन के द्वारा किया गया है–द्वितीयक आंकड़ो का संकलन भारत के जनगणना 2011 द्वारा प्रकाशित आंकड़े विभाग द्वारा व उपयोजना कार्यालय जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा उपलब्ध निम्न सामग्री द्वारा किया गया है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 92.39 लाख जनजाति के लोग है जो राज्य की कुल जनसंख्या का 13.48 प्रतिशत है जिससे जनजाति उपयोजना में 2001 के अनुसार 69.85 ग्रामीण 12.63 प्रतिशत नगरीय अनुसुचित जनजाति जनसख्या निवास करती है। सन् 2011 में अनुसूचित जनजाति व 73.17 प्रतिशत जनजाति जनसंख्या निवास करती है। उपयोजना क्षेत्र में भील, मीणा, डामोर, गरासिया, कथौड़ी, व सहरिया आदि जनजाति के व्यक्ति निवास करते है। राज्य की जनजातिओं के आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक तथा ग्रामीण विकास हेतु राज्य में जनजाति क्षेत्र विकास की स्थापना 1975 में की गई। राज्य की सभी जनजातिओं का संर्वागीण विकास हो सके। जिसमें राज्य सरकार ने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार योजना व उनके विकास हेतु क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। राज्य में अलग–अलग योजनाओं को निम्न नामो से पहचाना जाता है।

जनजाति क्षेत्र	जनजाति जनसंख्या	जनजाति प्रतिशत	राज्य में प्रतिशत
जनजाति उपयोजना क्षेत्र टी.पी.एस.	4188056	45.33	6.10
माड़ा क्षेत्र योजना	1830253	19.81	2.67
माडा कलस्टर क्षेत्र योजना	67451	0.73	0.09
सहरिया विकास क्षेत्र	102124	1.10	0.14
बिखरी हुई जाति	305065030	33.02	4.45
कुल योग	9238534	100	13.48

उपरोक्त सभी जनजाति क्षेत्र विकास की जनसंख्या अनुपात 20.01 प्रतिशत है। अकेले उपयोजना जनजाति क्षेत्र टी. एस. पी. में 45.33 प्रतिशत जनसंख्या है। साथ ही जनजाति उपयोजना में अजजा जनसंख्या 73.17 प्रतिशत है। उपयोजना में अजा की जनसंख्या का अनुपात 5 प्रतिशत से अधिक है।

1. जनजाति उपयोजना द्वारा विकास के कार्यक्रम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभाव ग्रस्त व रोजगारमुखी कृषि वनो आधारित या सरकारी नौकरी पेशा में आरक्षण पद्धति द्वारा कमजोर लोगों को मुख्य धारा में लाने के निम्न योजना या कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है।
2. मानव संसाधन शिक्षा की गुणात्मक परिवर्तन, व्यवसायिक शिक्षा के लिए मार्गदर्शन केन्द्र औद्योगिक प्रशिक्षण, शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, रोजगार प्रशिक्षण का संचालन, आश्रम, स्कूल, मॉ बाडी केन्द्र आवासीय विद्यालय, खेल छात्रावास, खेल प्रशिक्षण एवं छात्रावास व्यवस्था उच्च शिक्षा एवं राज्य सेवाएं व सिविल सर्विस च्डज, च्म्ज, प्प्ज, प्प्ड हेतु प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था
3. कृषि क्षेत्र की उत्पादकता कृषि जनजाति क्षेत्र का मुख्य रोजगार है इसमें न्यून क्षेत्र एवं अधिक उत्पादकता तकनीक का प्रयोग किया गया जिसमें (1) गहन कृषि (2) सब्जियों व फलों के पौधों का रोपण (3) कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान केन्द्र महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र (4) कृषि में आधुनिक यन्त्रों, बीज व तकनीकी का प्रयोग बढाना (5) कृषि प्रदर्शनियां (6) जल संसाधन का प्रयोग (7) गोल्डन मक्का बीज, खाद 50 किलों निःशुल्क वितरण करना।
4. वृक्षारोपण व वानिकी (1) पर्यावरण सुधार के लिए वनों का विस्तार, विकास की अति आवश्कता है। (2) व्यर्थ भूमि का विकास एवं प्रयोग, पहाडी क्षेत्र में विकास कार्य (3) सरकारी वृक्षारोपण एवं सामाजिक सुरक्षा का लक्ष्य पूर्ण करना। (4) जनजाति क्षेत्र में पौधशालाओं (नर्सरी) का विकास, बागवानी प्रशिक्षण।

5. पशु सम्पदा का विकास – पशु सम्पदा को आय एवं रोजगार से सम्बधित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किये गये (1) मत्स्य व कुक्कुट शालाओं का विकास प्रशिक्षण (2) पशु चिकित्सालय का विस्तार एवं शंकर नस्ल का विस्तार, (3) खरगोश पालन योजना व बकरी पालन योजना।
6. पेयजल व बकरी पालन योजना उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध करने के लिए माही बहुउद्देशीय परियोजना जाखम, सोम कमला, आम्बा परियोजना पूर्ण की गई। फलस्वरूप इस क्षेत्र सिंचाई सुविधाओं में विस्तार हुआ है।
7. पेयजल सुविधा में माही लिफ्ट परियोजना ढेबर, जाखम, सोम कमला अम्बा व अन्य पम्पसेट, ट्यूबवेल द्वारा जनजाति क्षेत्रों में पेयजल समस्या की कमी हुई है।
8. आधारभूत सुविधाओं का विकास इन सुविधाओं को सन्तुलित आधार पर विकसित करना ताकि विकास गति त्वरित हो सके। आधार सुविधा होती है लेकिन इनके शोषण व विदोहन की आवश्कता अति तीव्र है। अतः बेरोजगारी एवं गरीबी निवारण में प्राकृतिक संसाधनों का विकास अति आवश्यक है।
9. शोषण के विरुद्ध सुरक्षा जनजाति क्षेत्र को शोषण से मुक्त कराने की गहन आवश्कता आज भी है। यह वर्ग अशिक्षा एवं गरीबी के दुश्चक्र के कारण शोषित होता रहा है। अतः इस क्षेत्र के आरक्षण का लाभ यहां के जनजातियों को नहीं मिल पाया है, जो आज भी द्वितीयक श्रेणी नौकरियों तक की देय है जिनका लाभा माडा जनजातियों व अन्य जिलों के मीणा जनजाति वर्ग के लोग पहले से लाभ उठारहे है। राज्य सरकार में इस वजह से टी.एस.पी. उपयोजना क्षेत्र में निवास सामान्य व अन्य पिछडा वर्ग को भी इस योजना में शामिल किया गया है साथ ही एक अलग क्षेत्र मानकर स्थानिय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा ताकि उस क्षेत्र का विकास बढेगा।
10. योजनाओं व कार्यक्रमों का प्रसार व प्रसार से विकास– इस क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में जंगलों पहाडी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या को योजनाओं का पता नही रहता है, जिसकी जिम्मेदारी ग्राम स्तर व ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों की जिम्मेदारी व दायित्व से कर्तव्यों पालन कर ग्राम सभा या अन्य माध्यम से उचित प्रावधान किया जाए ताकि वास्तविक हकदार को लाभप्राप्त हो सके।

गरीबी निवारण के कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आठवीं योजना के अन्त तक सरकार ने अनेक निर्धनता निवारण कार्यक्रमों को अपनाया है जिनमें मुख्यतया सामुदायिक विकास योजना, पंचायती राज, लघु किसान विकास अभिकरण, सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास अभिकरण, काम के बदले अनाज, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम जवाहर रोजगार आदि प्रमुख है। भारतीय अर्थव्यवस्था से गरीबी को हटाने के लिए ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना अनिवार्य आवश्यकता है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास हेतु निम्न उपायों को अपनाया होगा:

1. ग्रामीण सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि प्रमुख सुविधाओं का विकास करना ।
2. व्यावहारिक लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास ।
3. स्थानीय पूँजी विनिर्माण परियोजनाओं विशेष रूप से ऐसी परियोजनाएँ जिनके द्वारा कृषि उत्पादकता में शीघ्र वृद्धि हो सके, जैसे लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ, नालियों का निर्माण, संग्रहण की सुविधा का विकास, स्थानीय परिवहन एवं सडकों का विकास आदि।
4. भूमि का कुशल वितरण, उसका विकास एवं व्यवस्थापन करना

निष्कर्ष

वर्तमान अध्ययन ने कथौड़ी जनजाति के सामाजिक और आर्थिक विकास को आकार देने में भूगोल की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है, जो एक विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (च्टज्ळ) है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के वन और पहाड़ी इलाकों में रहता है। कथौड़ी बस्तियों के स्थानिक अलगाव, पारिस्थितिक भेद्यता और कैटेचू जैसे वन संसाधनों पर ऐतिहासिक निर्भरता के साथ मिलकर, बुनियादी सेवाओं, सुरक्षित आजीविका और विकास के अवसरों तक उनकी पहुँच को गंभीर रूप से बाधित किया है। भौगोलिक वितरण, सामाजिक–आर्थिक संकेतकों और नीतिगत हस्तक्षेपों के विश्लेषण के माध्यम से, यह शोध पर्यावरणीय बाधाओं, संस्थागत हाशिए पर और सांस्कृतिक कारकों के बीच एक जटिल परस्पर क्रिया को प्रकट करता है। दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की कनेक्टिविटी की कमी और सरकारी कार्यक्रमों की खराब पहुँच ने कथौड़ी समुदाय के लिए गरीबी और बहिष्कार के चक्र को कायम रखा है। विस्थापन, भूमि अधिकारों की कमी, कम शैक्षिक प्राप्ति और शोषणकारी श्रम स्थितियों ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। हालाँकि, अध्ययन प्रगति और अवसर के क्षेत्रों पर भी प्रकाश डालता है। जिन क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप, जैसे समुदाय–आधारित आजीविका कार्यक्रम, शैक्षिक आउटरीच और स्वास्थ्य जागरूकता पहल को लागू किया गया है – अक्सर गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ – सामाजिक–आर्थिक उत्थान के संकेत स्पष्ट हैं। वन अधिकार अधिनियम (2006) जैसी योजनाओं की भूमिका, जब ठीक से लागू की जाती है, तो सुरक्षित भूमि स्वामित्व और टिकाऊ वन–आधारित आजीविका के माध्यम से कथौड़ी को सशक्त बनाने की क्षमता दिखाती है। कथौड़ी जनजाति के लिए सार्थक और सतत विकास प्राप्त करने के लिए, स्थान–आधारित, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और भागीदारी नियोजन दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। विकासात्मक नीतियों को कथोड़ियों द्वारा बसाए गए क्षेत्रों की भौगोलिक और पारिस्थितिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और सूक्ष्म–स्तरीय डेटा मैपिंग का एकीकरण आदिवासी क्षेत्रों में विकास नियोजन की सटीकता और प्रभावशीलता को काफी बढ़ा सकता है। निष्कर्ष रूप में, कथौड़ी जनजाति के सामाजिक और आर्थिक विकास को उनके भौगोलिक संदर्भ से अलग करके संबोधित नहीं किया जा सकता है। इस हाशिए पर पड़े समुदाय का भविष्य एक बहुआयामी रणनीति पर निर्भर करता है जो संरचनात्मक असमानताओं और स्थानिक नुकसान दोनों को संबोधित करती है। विकास विमर्श में भूगोल के महत्व को स्वीकार करके तथा तदनुसार हस्तक्षेप की रूपरेखा तैयार करके, नीति निर्माता कथौड़ी तथा इसी प्रकार की अन्य जनजातीय समुदायों के लिए समावेशी, समतापूर्ण तथा सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

संदर्भ

[1] गुडफेलो, आई., पौगेट–अबादी, जे., मिर्ज़ा, एम., जू, बी., वार्डे–फ़ार्ले, डी., ओज़ैर, एस., ... और बेंगियो, वाई. (2014)। जनरेटिव एडवर्सरियल नेट। न्यूरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम एडवांस में (पृष्ठ 2672–2680)।

[2] रेडफ़ोर्ड, ए., वू, जे., चाइल्ड, आर., लुआन, डी., अमोदेई, डी., और सुत्सकेवर, आई. (2019)। भाषा मॉडल अप्रशिक्षित मल्टीटास्क ओपनएआई।

[3] रमेश, ए., पावलोव, एम., गोह, जी., ग्रे, एस., वॉस, सी., रेडफ़ोर्ड, ए., ... और सुत्सकेवर, आई. (2021)। ज़ीरो–शॉट टेक्स्ट–टू–इमेज जेनरेशन। मशीन लर्निंग पर 38वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही में।

[4] टूवरन, एच., लावरिल, टी., इज़ाकार्ड, जी., मार्टिनेट, एक्स., लाचॉक्स, एम. ए., लैक्रोइक्स, टी., ... और जेगौ, एच. (2023)। एलएलएएमएरू ओपन और कुशल फाउंडेशन लैंग्वेज मॉडल। ंतग्पअ प्रीप्रिंट ंतग्पअरू 2302.13971।

[5] जू, एल., रेन, जे., लियू, सी., वांग, एल., और किउ, एक्स. (2020)। मशीन लर्निंग के लिए डेटा संश्लेषण एक सर्वेक्षण। ंतग्पअ प्रीप्रिंट arXiv:2006.01875।

[6] फ़िरड–अदार, एम., क्लैंग, ई., अमिताई, एम., गोल्डबर्गर, जे., और ग्रीनस्पैन, एच. (2018)। बेहतर लिवर घाव वर्गीकरण के लिए ळ।छ का उपयोग करके सिंथेटिक डेटा वृद्धि। ट्रांजेक्शन ऑन मेडिकल इमेजिंग, 38(3), 677–685।

[7] किट्ज़मैन, जे., पासचेन, जे., और ट्रीन, ई. (2018)। विज्ञापन में कृत्रिम बुद्धिमत्तारू कैसे विपणक ग्राहक अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए एआई का लाभ उठा सकते हैं। जर्नल ऑफ़ एडवरटाइजिंग रिसर्च, 58(3), 263–267।

[8] फ्लोरिडी, एल., और चिरियाट्टी, एम. (2020)। ळच्ज्–3: इसकी प्रकृति, दायरा, सीमाएँ और परिणाम। माइंड्स एंड मशीन्स, 30(4), 681–694।

[9] कर्रास, टी., लेन, एस., और आइला, टी. (2019)। जनरेटिव एडवरसैरियल नेटवर्क के लिए एक स्टाइल–आधारित जनरेटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर विज़न और पैटर्न रिकॉग्निशन पर IEEE@CVF कॉन्फ्रेंस की कार्यवाही में (पृष्ठ 4411–4410)।

[10] टोर्गो, एल. (2017)। आर के साथ डेटा माइनिंग केस स्टडी के साथ सीखना। सीआरसी प्रेस।

[11] भल्ला, एल.आर., राजस्थान का भूगोल, कुलदीप पब्लिकेशन, हाउस, जयपुर, 2014

[12] राजस्थान सरकार, अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याणकारी योजनाऐं, टी. आर. आई, 2011–12

[13] डॉ. वर्मा, सावलिया बिहारी, ग्रामीण गरीबी उन्मुलन, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन नई दिल्ली 2011

[14] सिह, शिवशंकर,भारत में समन्वित ग्रामीण विकास एव नियोजन, नई दिल्ली 2008

[15] शर्मा, रेखा ,ग्रामीण विकास एवं नियोजन रावत पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2012

[16] आशुतोष ठाकुर, ट्राईबल डेवलपमेन्ट एण्ड ईट्स पेराडोक्स 2001

[17] जनगणना सेन्सस, 2011

[18] राजस्थान सरकार, बजट घोषणा मार्च 2014

सन्तोष कँवर, शोधार्थी अपेक्स विश्वविद्यालय,जयपुर

डॉ चन्द्रशेखर जैमन, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग

Published on April 30, 2025.